गुरयेव सिंह, जे. के समक्ष

श्रीमती शकुंतलाभनोत और अन्य -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी

1991 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10540

13 मई 2011

भारत का संविधान, 1950 -अनुच्छेद 14,16 और 226/22 7 -पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 -धारा 41-ए, 42 और 43 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 1974 -नियम 14 - पंजाब सिविल सेवा (पदोन्नति) आशुलिपिकों/स्टेनो-टाइपिस्टों की) नियमावली, 1961-नियम 5 - क्या स्टेनो-टाइपिस्ट लिपिक पक्ष पर पदोन्नति के हकदार हैं - परमादेश जारी - पात्र स्टेनो-टाइपिस्ट और क्लर्क की अनुमानित वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश - परिणामी लाभ प्रदान करें।

निर्णय दिया गया कि परिणामतः यह याचिका स्वीकार की जाती है। बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह पात्र स्टेनो-टाइपिस्ट और क्लर्कों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए उनकी उप-विभागीय क्लर्क के रूप में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 के मामले पर विचार करें। और, यदि पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें उस तारीख से पदोन्नत करने के लिए, उनसे कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नत किया गया था और उन्हें पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाने की तारीख से उनके वेतन को निर्धारित करने का परिणामी लाभ दिया गया था। यह लाभ पेंशन के प्रयोजनों के लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा। हालाँकि, वे किसी बकाया आदि के हकदार नहीं होंगे।

(पैराग्राफ 8)

याचिकाकर्ता नंबर 2 सी.एम. के वकील अनुराग गोयल।

चोपड़ा, वकील, याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 के लिए

के.सी. प्रतिवादी नंबर 1 के लिए

भाटिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए वकील सी.बी. गोयल

गुरदेव सिंह, जे.

1. यह सिविल रिट याचिका श्रीमती द्वारा दायर की गई है। शकुंतला भनोट, जय किशन शर्मा, बिजेंद्र सिंह और बोध राज, याचिकाकर्ता, जिन्हें शुरुआत में प्रतिवादी नंबर 2-बोर्ड में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, एक परमादेश जारी करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वे सब डिविजनल क्लर्क के पद के लिए उन पर विचार करें। वह तारीख जब क्लर्कों को, जो उनसे कनिष्ठ थे, पदोन्नत किया गया था और वरिष्ठता, वेतन और उस पर ब्याज सहित उससे होने वाले परिणामी लाभ जारी करने के लिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 1974 (संक्षेप में "नियम") द्वारा शासित हो रहे हैं और उन नियमों के अनुसार, स्टेनो-टाइपिस्ट के पद से अगली पदोन्नति जूनियर स्केल के पद पर होती है। स्टेनो के संवर्ग में आशुलिपिक। हरियाणा राज्य में कार्यरत स्टेनो-टाइपिस्ट भी लिपिक पक्ष यानी उप-विभागीय क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। बोर्ड ने क्लर्कों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए हैं। स्टेनो-टाइपिस्टों को सब-डिविजनल क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हालाँकि, उन नियमों के नियम 14 के अनुसार, कर्मचारियों के संबंध में, जो नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, उन्हें पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत हरियाणा राज्य में आवेदन के रूप में निपटाया जाना है। उन नियमों के अनुसार, वे लिपिक वर्ग में पदोन्नति के हकदार हैं। मार्च, 1987 के महीने में, बोर्ड ने लिपिकीय पक्ष पर स्टेनो-टाइपिस्टों को 75% की सीमा तक पदोन्नति प्रदान करने का संकल्प लिया। वे लिपिक वर्ग में अपनी पदोन्नति में रुचि रखते हैं। बोर्ड में क्लर्कों की कमी के कारण, कुछ उम्मीदवार, जिन्हें वर्ष 1980 में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में चुना गया था, को क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें उप-विभागीय क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। उनसे पहले बोर्ड में शामिल हुए। उन्होंने

सब-डिविजनल क्लर्क के रूप में अपनी पदोन्नति के लिए कई अभ्यावेदन दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। स्टेनो-टाइपिस्ट होने के कारण वे अयोग्य हैं, इस आधार पर उन्हें सब-डिविजनल क्लर्क के रूप में पदोन्नत न करने का बोर्ड का कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

2. याचिकाकर्ताओं के दावे का बोर्ड ने विरोध किया। लिखित बयान में, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 42 के तहत वैकल्पिक उपाय थे और रिट याचिका केवल उस आधार पर खारिज करने योग्य थी। बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार, पदोन्नति के विभिन्न चैनल हैं और स्टेनो-टाइपिस्ट के पद से जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर तक पदोन्नति का चैनल है। पंजाब सिविल सेवा नियम, 1961 बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर लागू नहीं होता है और अधिनियम की धारा 43 के तहत राज्य सरकार है, जो उन कर्मचारियों के लिए नियम बनाने का अधिकार रखती है। बोर्ड स्वयं ऐसे कोई नियम नहीं बना सकता। एक प्रस्ताव पारित कर सेवा नियमों में प्रावधान करने की अनुशंसा की गयी थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा उस प्रस्ताव/संकल्प को स्वीकार नहीं किया गया है. स्टेनो-टाइपिस्ट और क्लर्क के अलग-अलग कैडर हैं और वे अलग-अलग वेतनमान और विशेष वेतन के हकदार हैं और इसके लिए स्टेनो-टाइपिस्ट और क्लर्क की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की जा सकती है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट की नियुक्ति का हवाला देकर मामले को उलझाने की कोशिश की है. चूँकि अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ हैं, इसलिए याचिकाकर्ता क्लर्कों की तुलना में किसी भी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते।

3. यह याचिका याचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से वापस ले ली गई थी और इसे याचिकाकर्ता के आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2002 के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 3 के वकील ने उस याचिकाकर्ता की ओर से इस याचिका पर जोर नहीं दिया है, जैसा कि उसके अनुसार है उन्हें निजी सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है, याचिका केवल याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 की ओर से दायर की गई है।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

4. इन याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस मामले पर नियम मौन हैं, वे हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब सिविल सेवा नियमों और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शासित हो रहे हैं। अनुलग्नक पी-2 के अनुसार, वे सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हो गए और इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड को पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए क्लर्कों के साथ गिनती की जाने वाली स्टेनो-टाइपिस्टों की वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता थी। बोर्ड ऐसा करने में विफल रहा और राज्य सरकार के उस निर्देश का घोर उल्लंघन करते हुए, इन याचिकाकर्ताओं के बहुत बाद नियुक्त किए गए क्लर्कों को सब-डिविजनल क्लर्क के पद पर पदोन्नत कर दिया। नियमों में संशोधन के बिना भी, याचिकाकर्ता उप-विभागीय क्लर्कों के रूप में पदोन्नति के हकदार थे, जारी किए गए निर्देशों के मद्देनजर, अनुलग्नक पी-2, क्योंकि पंजाब सिविल सेवा नियम इस तथ्य के आधार पर लागू होने थे कि नियम 14 नियमों में प्रावधान है कि जिन मामलों पर नियम मौन हैं, उन पर पंजाब सिविल सेवा नियम, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है, लागू होना था। इन परिस्थितियों में, बोर्ड को याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 पर सब डिविजनल क्लर्क के रूप में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए विचार करने और उन्हें डेल से पदोन्नत करने के लिए, उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत करने के लिए परमादेश जारी किया जाए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि बोर्ड राज्य सरकार द्वारा जारी अनुलग्नक पी-2 के निर्देशों से बाध्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड द्वारा संशोधन के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है। उन निर्देशों के अनुसार नियमों को राज्य सरकार द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया और सेवा नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेनो-टाइपिस्ट क्लर्कों की तुलना में एक अलग कैडर का गठन करते हैं और पदोन्नति के लिए अलग-अलग चैनल हैं और स्टेनो-टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नति के हकदार हैं। और केवल क्लर्क ही सब-डिविजनल क्लर्क के रूप में पदोन्नत होने के हकदार हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता उप-विभागीय क्लर्क के रूप में अपनी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते।

6. उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 द्वारा की गई दलीलें कि बोर्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों से बाध्य नहीं है, लिखित बयान में दिए गए तर्कों के विपरीत है, जिसमें यह दलील दी गई है कि अधिनियम की धारा 43 के तहत केवल राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है. यहां तक कि वकील द्वारा दिया गया दूसरा तर्क यह है कि बोर्ड द्वारा जारी और स्वीकार किए गए निर्देश, नियमों में परिवर्तित नहीं हुए हैं, उन्हें लागू/स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वे निर्देश इस आशय के थे कि पंजाब सिविल सेवा (आशुलिपिक/आशुलिपिक की पदोन्नति) नियम, 1961 के नियम 5 के अनुसार, लिपिक/आशुलिपिक/आशुलिपिक को सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र बनाया गया है। स्टेनो-टाइपिस्टों की वरिष्ठता सूची को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले क्लर्कों के साथ गिना जाएगा। स्थिति स्पष्ट की गई। -बोर्ड के सचिव द्वारा बोर्ड कर्मचारियों के नियमों में संशोधन के संबंध में चर्चा के बाद परिशिष्ट पी-3 के अनुसार। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उस समय बोर्ड कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सरकार ने पहले ही इस उद्देश्य के लिए नियम बना दिए थे और बोर्ड को सूचित कर दिया था। -अनुलग्नक पी-2 देखें। यदि बाद में, बोर्ड ने अपने द्वारा पारित संकल्प के मद्देनजर सेवा नियमों में संशोधन के लिए राज्य सरकार के साथ पत्राचार करने का प्रयास किया। उपरोक्त निर्देशों और नियमों को शामिल करते हुए, यह सिर्फ व्यर्थ की कवायद थी और ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को लटकाने और कर्मचारियों को उनके हक से वंचित करने के लिए ऐसा किया गया है। नियमों के नियम 14 के अनुसार, जिस मामले पर नियम मौन हैं, बोर्ड को हरियाणा राज्य में लागू पंजाब सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित किया जाना है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार, जैसा कि अनुलग्नक पी-2 में शामिल है, स्टेनो-टाइपिस्टों को सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए क्लर्कों के बराबर किया जाना था और उस उद्देश्य के लिए, बोर्ड को स्टेनोग्राफरों और की एक काल्पनिक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करनी थी। लिपिकों को यह निर्धारित करने के लिए कि पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए उनमें से कौन वरिष्ठ है। बोर्ड राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा अधिनियम की धारा 41 के आधार पर कौन से निर्देश उस पर बाध्यकारी हैं।

7. उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 के वकील के अनुसार रिट परमादेश जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन नहीं दिया गया था। अनुलग्नक पी-5, अभ्यावेदन है और यह याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 द्वारा बनाया गया था। जब एक अभ्यावेदन समान स्थिति वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया था, और इसे बोर्ड के ध्यान में लाया गया था कि निर्देशों/नियमों के अनुसार। उप-विभागीय क्लर्कों के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए स्टेनो-टाइपिस्टों को क्लर्कों के बराबर माना जाना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 द्वारा ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। बोर्ड था याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 द्वारा लिखित अभ्यावेदन देकर मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद निर्देशों/नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। समान स्थिति वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तरह का अभ्यावेदन न देना परमादेश रिट जारी करने में कोई बाधा नहीं है।

8. परिणामतः यह याचिका स्वीकार की जाती है। बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह पात्र स्टेनो-टाइपिस्टों और क्लर्कों की एक अनुमानित वरिष्ठता सूची तैयार करके उप-विभागीय क्लर्कों के रूप में उनकी पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 के मामले पर विचार करें ताकि उनकी तुलना निर्धारित की जा सके। वरिष्ठता और, यदि पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें उस तिथि से पदोन्नत करने के लिए, उनसे कनिष्ठ क्लर्कों को पदोन्नत किया गया था और उन्हें उनके वेतन को निर्धारित करने का परिणामी लाभ दिया गया था।

   जिस तारीख को वे पात्र पाए गए प्रमोशन के लिए. यह लाभ पेंशन के प्रयोजनों के लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा। हालाँकि, वे किसी भी बकाया आदि के हकदार नहीं होंगे। यह कार्य बोर्ड द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा